

राजपत, हिमाचल प्रदेश

(असाधारण)

हिमाचल प्रदेश राज्यशासन द्वारा प्रकाशित

शिमला, मंगलवार, 4 श्रन्तूबर, 1988/12 श्राश्विन, 1910

हिमाचल प्रदेश सरकार

AGRICULTURE DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 29th August, 1988

No. Agr. A (4)-9/86.—In continuation of this Department notification of even number, dated the 16th August, 1988, the Governor, Himachal Pradesh is pleased to order that the terms and conditions for the payment of TA/DA in respect of Non-official Members of the Himachal Pradesh Marketing Board will be as per Annexure "A".

The expenditure on this account is to be borne by the Himachal Pradesh Marketing Board.

मूल्य: 20 पैसे ।

(2417)

ANNEXURE "A"

- 1. T. A. & D. A. To Non-official Members of the Board.
- 1. Travelling Allowance:—(i) Journey by rail.—They will be treated at par with Government servants of the first grade, and will be entitled to actual rail fare of the class of accommodation actually used but not exceeding the fare in which the Government servants of the first grade are normally entitled, i.e. accommodation of the highest class by whatever name it may be called provided in the railway by which the journey is performed.
- (ii) Journey by road.—They will be entitled to actual fare for travelling by taking single seat in a public bus, and if the journey is performed by motor cycle/scooter, mileage allowance at 60 paise per km. for plain areas and 80 paise per km. in hilly areas, or if journey is performed by full taxi/own car, the member will be entitled to mileage allowance at Rs. 2.00 per km. in respect of journeys in the plains and Rs. 2.50 per km. in the hills.
- (iii) In addition to the actual fare of mileage as per item: (i) & (ii) above, member shall draw daily allowance for the entire absence from his permanent place of residence beginning with departure from the place and ending with return to that place, at the same rate subject to the same terms and conditions as apply to Grade-I officers of the State Government.
- 2. Daily Allowances—(i) Non-official members will be entitled to draw daily allowance for each day of the meeting at the highest rates as admissible to a Government servant of the first grade for respective locality.
- (ii) In addition to daily allowance for the day(s) of the meeting, a member shall also be entitled to daily allowance for halt on tour and out-station in connection with the affairs of the Committee as under:—
 - (a) If the absence from headquarters does not exceed 6 hours

.. Nil.

(b) If the absence from headquarters exceed 6 hours but does not exceed 12 hours

. 70%.

(c) If the absence from headquarters exceed 12 hours

Full.

3. Conveyance Allowance.—A member, resident at a place where the meeting of the Committee is held will not be entitled to travelling and daily allowance on the scales indicated above, but will be allowed only the actual cost of conveyance hire, subject to maximum of Rs. 10.00 per day. Before the claim is actually paid for, the Controlling Officer should verify the claims and satisfy himself after obtaining such details as may be considered necessary, that the actual expenditure was not less than the amount claimed.

If such a member uses his own car, he will be granted mileage allowance, at the rates admissible to officers of the first grade subject to a maximum of Rs. 10.00 per day.

4. The members will be eligible for travelling allowance for the journey actually performed in connection with the meetings of the Committee, from and to the places of their permanent residence to attend a meeting of the Committee or return to the place other than the place of his permanent residence after the termination of the meeting. Travelling allowance shall be worked out on the basis of the distance actually

travelled or the distance between the place of permanent residence at the venue of the meeting whichever is less.

- 5. The provision of rules 4.17 & 6.1 of the Himachal Pradesh Treasury Rules will apply mutatis mutandis in the case of over payment made on account of travelling allowance to non-official members.
- 6. Official members.—The official members shall be entitled to the travelling and daily allowance admissible to them according to the rules governing them.

By order,
Sd/Financial Commissioner-cum-APC.

सहकारिता विभाग

ग्रधिस्चना

शिमला-2, 23 सितम्बर, 1988

संख्या 5-1/70 कोप (एस)-ii.—हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश वेयर हाऊस ऐक्ट, 1976 की धारा 35 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए इस विभाग की ग्रिधिसूचना संख्या 5-1/70-कोप-ii, तारीख 13 ग्रागस्त, 1987 द्वारा तारीख 1 दिसम्बर, 1987 के राजपत, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित, हिमाचल प्रदेश भाण्डागार नियम, 1987 में निम्नलिखित संशोधन करते हैं, ग्रथात:—

- 1. संक्षिप्त नाम ग्रौर प्रारम्भ.—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश भाण्डागार (संशोधन) नियम, 1988 है।
 - (2) ये नियम तुरन्त प्रवृत्त होंगे।
- 2. नियम 10 का संशोधन.—हिमाचल प्रदेश भाण्डागार नियम, 1987 (जिसको इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है) में शब्द "की" तथा शब्द "संसूचना" के बीच शब्द "भाण्डागार-पाल को" स्रन्त: स्थापित किए जाऐंगे।
- 3. नियम 19 का संशोधन.--उक्त नियमों के नियम, 19 में शब्द "के लिए" के स्थान पर शब्द "समय से" प्रतिस्थापित किए जाएंगे।

म्रादेश द्वारा, एस ० एस ० सिद्धु, सचिव [Authoritative English text of Government notification number 5-1/70-Co-op (S)-Vol. II, dated 23-9-88 is hereby published in the Rajpatra, Himachal Pradesh as required Article 348(3) of the Constitution of India].

CO-OPERATION DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shirnla-2, the 23rd September, 1988

- No. 5-1/70-Co-op. (S)-Vol. II.—In exercise of the powers conferred by section 35 of th Himachal Pradesh Warehouse Act, 1976, the Governor, Himachal Pradesh is pleased to make the following amendments in the Himachal Pradesh Warehouses Rules, 1987 published in the Rajpatra. Himachal Pradesh, dated 1st December, 1987 vide this department notification No. 5-1/70-Co-op (S)-II, dated the 13th August, 1987, namely:—
- 1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Himachal Pradesh Warehouses (Amendment) Rules, 1988.
 - (2) These rules shall come into force at once.
- 2. Amendment of rule 10.—In rule 10 of the Himachal Pradesh Warehouses Rules, 1987 (hereinafter called the "said rules") after the words "such orders", the words "to the warehouseman" shall be added,
- 3. Amendment of rule 19.—In rule 19 of the said rules, between the words "from" and "making" the words "the time of" shall be inserted.
- 4. Amendment of rule 22.—In clause (d) of sub-rule (1) of rule 22 of the said rules, for the existing words "constructed" and "a round" the words "stacked" and "around" respectively shall be substituted.

By order, S. S. SIDHU, Secretary.

गृह विभाग

ग्रधिसूचना

शिमला-171002

संख्या 11/6/67-गृह (ए).—हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, मैनोवर फील्ड फायरिंग एवं आरटिलरी प्रैक्टिस अधिनियम, 1938 (1938 का पांचवा अधिनियम) की धारा 9 की उप-धारा (3) क अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए जैसा कि उक्त अधिनियम की धारा 9 की उप-धारा (4) में अपेक्षित है इस अधिनियम की धारा 9 की उप-धारा (2) के अधीन उन क्षेत्रों म जोकि हिमाचल प्रदेश सरकार की अधिसूचना संख्या 11-6-67 गृह (ए)भाग-II दिनांक 3-5-88 जोकि राजपत्र (असाधारण), हिमाचल प्रदेश में 18 जून, 1988 के अंक में प्रकाशित हुई थी निर्दिष्ट के किए गए हैं, में निम्नलिखित अवधि क दौरान पूर्व परिभाषित क्षेत्र में फील्ड फायरिंग तथा आरटिलरी अभ्यास

रने हेतु प्राधिकृत करने के निश्चय को सरकारी राजपत्न में इस ग्राशय की ग्रधिसूचना उन लोगों की सू<mark>चना हे</mark>तु गोकि इस के द्वारा प्रभावित होना सम्भावित हैं, सहर्ष प्रकाशित करते हैं ।

सितम्बर, 1988	ग्रन्तूबर, 1988	नवम्बर, 1988
6्से 8 तक	3 से 5 तक	1 से 3 तक
12 से 14 तक	7 से 8 तक	7 से 8 तक
15 से 16 तक	11 से 13 तक	10 से 12 तक
20 से 22 तक	17 से 18 तक	15 से 17 तक
27 से 29 तक	20 से 22 तक	21 से 23 तक
,	25 से 2 6 तक	25 से 26 तक
	28 से 31 तक	29 से 30 तक
दिसम्बर, 1988 ———————	जनवरी, 1989	फरवरी, 1989
1 से 3 तक	2 से 7 तक	2 से 4 तक
6 से 8 तक	9 से 14 तक	7 से 8 तक
12 से 13 तक	16 से 21 तक	10 से 11 तक
15 से 17 तक	23 से 25 तक	13 से 15 तक
20 से 22 तक	30 स 31 तक	17 से 18 तक
26 स 27 तक		20 से 22 तक
28 से 30 तक		24 से 25 तक
मार्च, 1989	ग्रप्रैल, 1989	मई, 1989
2 से 4 तक	3 से 5 तक	
7 से 8 तक	7 से 8 तक	5 से 6 तक
10 से 11 तक	10 से 11 तक	8 से 9 तक
13 से 14 तक	13 से 14 तक	11 से 12 तक
16 से 17 तक	17 से 18 तक	15 से 17 तक
27 से 28 तक	20 से 21 तक	16 से 20 तक
30 से 31 तक	24 से 25 तक	22 से 23 तक
	27 से 28 तक	25 से 27 तक
		29 से 30 तक
जन, 1989		

जून, 1989

1 से 3 तक 6 से 8 तक 12 से 14 तक 17 से 20 तक 22 से 24 तक 26 से 27 तक

29 से 30 तक .

ग्रादेश द्वारा, कंवर शमशेर सिंह, ग्रायुक्त एवं सचिव ।

उद्यान विभाग

ग्रधिसूचना

शिमला-2, 6 फरवरी, 1988

संख्या उद्यान-क(3)4/81-11.—भारतीय संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश, लोक सेवा आयोग हिमाचल प्रदेश की सहमति से हिमाचल प्रदेश उद्यान विभाग में अतिरिक्त निदेशक उद्यान श्रेणी-I (राजपन्नित) वेतनमान रुपये 2300—2500 पद के लिए भर्ती एवं पदोन्नित नियम जो इस विभाग की अधिसूचना सं0 उद्यान-क (3)4/81-II, दिनांक 3-9-87 द्वारा अधिसूचित किए गए थे को निष्प्रभावित करते हुए इस अधिसूचना में संलग्न (अनुबन्ध-II) के अनुसार अतिरिक्त निदेशक वर्ग प्रथम (राजपन्नित) के भर्ती एवं पदोन्नित नियम सहर्ष बनाते हैं।

राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश इसके आगे इस विभाग द्वारा इस पद के लिए भर्ती एवं पदोन्नित नियम अधिसूचना सं 0 25-5/69-होर्ट (मैक्ट), दिनांक 19-12-71 तथा समय-समय पर इन नियमों में किए गए संशोधन अधिसूचित को निरसन करने की सहर्ष अनुमित प्रदान करते हैं बशर्ते कि यह निरसन पहले बनाए गए भर्ती एवं पदोन्नित नियमों के अन्तर्गत हुई कार्यवाही पर असर नहीं डालेगा या उन नियमों के अन्तर्गत की गई कार्यवाही उन नियमों के अनुसार मान्य होगी।

- 1. संक्षिप्त नाम ग्रौर प्रारम्भ.—(1) यह नियम हिमाचल प्रदेश उद्यान विभाग के वर्ग प्रथम (राजपन्नित) सेवाएं नियम, 1988 कहलायेंगे ।
 - (2) यह नियम हिमाचल प्रदेश सरकार के राजपत्र में प्रकाशित होने की तिथि से लागू होंगे।

त्रनुबन्ध-II

हिमाचल प्रदेश सरकार, उद्यान विभाग में श्रेणी-। (राजपत्रित) सेवाएं नियम, 1988

- 1. पद का नाम
- 2. पद की संख्या
- 3. वर्गीकरण
- 4. वेतनमान
- 5. क्या पद प्रवरण ग्रथवा ग्रप्रवरण है ?
- 6. सीधी भर्ती के लिये ग्रायु सीमा

श्रितिरिक्त निदेशक उद्यान । एक श्रेणी-I (राजपनित) । रुपये 2300—2500 । प्रवरण । 45 वर्ष तथा इस से कम:

उपबन्धित है कि सीधी भर्ती के लिये ग्रिधिकतम स्रायु सीमा उन उम्मीदवारों पर लाग् नहीं होगी जो पहले ही तदर्थ या अनुबन्ध के स्राधार पर सरकारी सेवा में कार्यरत हों:

ग्रागे उपबन्धित है कि तदर्थ या प्रनुबन्ध के ग्राधार पर नियुक्त उम्मीदवार यदि नियुक्ति तिथि की ग्रधिकतम ग्रायु सीमा पार कर गया हो, तो उसे निर्धारित ग्रायु सीमा म उस ग्राधार पर छूट नहीं दी जायेगी:

ग्राग उपबन्धित है कि श्रनुसूचित जातियों/ग्रनुसूचित जन-जातियों क उम्मीदवारों तथा ग्रन्य वर्गो क व्यक्तियों क लिय उच्चतम श्रायु सीमा में देय छूट उतनी है, जितनी हिमाचल प्रदेश सरकार क सामान्य श्रयवा विशेष ग्रादेशों के श्रन्तर्गत ग्रनुमत है: त्रागे उपबन्धित है कि सार्वजनिक क्षेत्र में निगमों तथा स्वायत निकायों के लिए सभी कर्मचारियों को जो इन सार्वजनिक क्षेत्र के निगम तथा स्वायत निकायों के प्रारम्भिक गठन के समय इनमें अन्तर्लीत होने से पूर्व सरकारी कर्मचारी थे, की भी सरकारी कर्मचारियों की भांति सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा में छुट होगी। इस प्रकार की छूट सार्वजनिक क्षेत्र के निगमों तथा स्वायत निकायों के उन कर्मचारियों को उपलब्ध नहीं होगी जो उनत निगमों, स्वायत निकायों द्वारा बाद में भर्ती किये गये थे/हों, और इन सार्वजनिक क्षेत्र के निगमों/स्वायत निकायों के प्रारम्भिक गटन के बाद अन्तिम रूप से इन निगमों/स्वायत निकायों में अन्तर्लीत हो गये हों। टिप्पणी—1. सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा, आयोग द्वारा आवेदन-पत्र प्राप्त करने के लिए नि। च्चत श्रान्तम तिथि गिनी जायेगी।

2. सीधी भर्ती की स्थितियों में ग्रन्यथा विशिष्ट योग्यता प्राप्त उम्मीदवार के लिये श्रायु सीमा तथा श्रन्भव स राम्बन्धित योग्यताग्रों में श्रायोग के विवेकानुसार छूट देय होगी।

7. सीधी भर्ती के लिये कम से कम शैक्षणिक योग्यता तथा स्रनिवार्य प्रत्य स्रावश्यक योग्यतायं।

श्रनिवार्य :

- (i) उद्यान में एम0 एस0 सी0 तथा इसके साथ पोमोलोजी में विशेषता या इसके समकक्षा
- (ii) पहाड़ी क्षेत्र के उद्यान विकास में कम से कम 10 वर्ष का ग्रनुभव तथा इसके साथ प्रशासनिक उत्तरदायी पद पर 5 वर्ष का ग्रनुभव।

वांछनीय :

हिमाचल प्रदेश के रीति-रिवाज, भाषा और सस्कृति का ज्ञान तथा प्रदेश की विशेष परिस्थितियों में नियुक्ति के लिए उपयुक्तता ।

प्रायुः नहीं ।

शैक्षणिक योग्यता : लागू होगी ।

दो वर्ष की परिवीक्षा अवधि जिसको कि सक्षम प्राधि-कारी के लिखित आदेश द्वारा विशेष परिस्थितियों में अधिकतम केवल एक वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है। पदोन्नति अन्यथा सीधी भर्ती द्वारा ।

संयुक्त निदेशक उद्यान/परियोजना निदेशक में से पदोन्नित द्वारा तथा कम से कम तीन वर्ष की नियमित सेवा श्रेणी-I श्रिधकारी के रूप में विभाग में की हो, श्रौर नियमित नियक्ति के पूर्व यदि कोई 31-12-83 तक श्रपेक्षित पद पर तदर्थ

- 8. क्या प्रायु व शैक्षणिक योग्यता जिसका वर्णन सीधी भर्ती के लिये किया गया है पदोन्नित के लिये भी नागू होगी ?
- 9. परिवीक्षा की ग्रवधि, यदि कोई हो
- 10. भर्ती की प्रणाली क्या सीधी प्रथवा पदोन्नित द्वारा प्रथवा प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण द्वारा तथा विभिन्न ढंगों द्वारा रिक्त स्थानों को भरने की प्रतिशतता।
- 11. पदोन्नित/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण द्वारा भर्ती के मामले पर वह वेतनमान जिसमें से पदोन्निति/ प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण किया जाना है।

सेवा की गई हो या 5 वर्ष की नियमित सेवा श्रेणी-(जिसमें 31-12-83 तक की गई तदर्थ सेवा शामिल हो) तो पदोन्नित के लिये निर्धारित कार्यकाल श्रविध में एसी सेवा की श्रविध गिनी जायेगी।

पदोन्नित कें लिये पात्र संयुक्त निदेशक उद्यान/ परियोजना निदेशक की संयुक्त वरिष्ठता सूची नियमित/ तदर्थ केंद्रा जो कि 31-12-83 तक की हो के स्राधार पर तैयार की जायेगी।

टिप्पणी 1.—पदोन्नित के सभी मामलों में नियमित नियुक्ति से पूर्व यदि कोई 31-12-83 तक अपेक्षित पद पर कार्य सेवा की गई हो तो पदोन्नित के लिये निर्धारित कार्यकाल अवधि म ऐसी सेवा की अवधि को गिना जायगा जैसा कि नियमों में निर्धारित है बधार्ते कि:—

(क) उपरोक्त शर्तों को मध्यनजर रखत हुये सभी मामलों पर जो सेवा की एक कनिष्ठ प्रत्याशी 31-12-83 तक की गई तदर्थ सेवा को मिला कर पदोन्नति के लिय योग्य हो जाता है तो वह सभी प्रत्याशी जो तत्सम्बन्धी वर्ग-पंवर्ग में इससे विष्ठ होंगे वह सभी विचारणीय होंगे तथा कनिष्ठ प्रत्याशी से विष्ठ समझे जायोंगे:

उपबन्धित है कि वे सभी प्रत्याशी जो पदोन्नित हें व कम से कम तीन वर्ष की न्यूनतम सरकारी सेवा श्रविध या भर्ती एवम् पदोन्नित नियमानुसार जो भी निर्धारित सेवा की श्रविध हो, दोनों में से जो भी कम हो रखते हों:

श्रामे उपबन्धित है कि यदि कोई कर्मचारी/प्रत्याशी पदोन्नित के लिय उपरोक्त उपबन्धों के श्रनुसार श्रनुपयुक्त/श्रयोग्य पाया जाता है तो ऐसी परिस्थित में उससे कनिष्ठ प्रत्याशी भी पदोन्नित के लिये श्रयोग्य समझे जायेंगे।

(ख) इसी प्रकार स्थाईकरण के सभी मामलों के लिये भी 31-12-83 तक की गई तदर्थ सेवा नियमित नियुक्ति से पहले यदि कोई हो तो ऐसी सेवा को कार्यकाल ग्रविध में जोड़ा जायेगा: उपबन्धित है कि इस प्रकार तदर्थ सेवा समिलित करकें स्थाईकरण करनें पर भी परस्पर वरिष्ठता म परिवतन न ग्राने पायें।

(ग) 31-12-83 के उपरान्त की गई तदर्थ सेवा को स्थाईकरण या पदोन्नति के लिये नहीं गिना जायेगा।

टिप्पणी 2. — जब कभी नियम 2 के श्रधीन पदों की संख्या में वृद्धि की जाती है तो सरकार

12. यदि विभागीय पदोन्नति समिति विद्यमान है, तो इसकी संरचना क्या है ?

13. परिस्थितियां जिसमें भर्ती के लिये हिमाचल प्रदेश लोक सेवा ग्रायोग का परामर्श लिया जायेगा ।

14. सीधी भर्ती के लिये ग्रावश्यक योग्यतायें

15. सी जी भर्ती द्वारा नियुक्ति हेतु चयन

16. ग्रारक्षण

17. शिथिल करने की शक्ति

द्वारा हिमाचल प्रदेश लोक सेवा ग्रायोग के परामर्श से नियम 10 तथा 11 के उपबन्धों में संशोधन किये जायेंगे।

जैसा कि समय-समय पर सरकार द्वारा गठित की जायेंगी

जैसा कि विधि के ग्रधीन ग्रपेक्षित है।

उपर्युक्त या पद सेवा के लिये उम्मीदवार का निम्न-लिखित का होना ग्रावण्यक है:—

(क) भारतीय नागरिक, या

(ख) नेपाल की प्रजा, या

(ग) भूटान की प्रजा,या

(घ) विस्थापित तिब्बती जोिक 1 जनवरी, 1962 से पूर्व भारत में स्थापी निवास के उद्देश्य से ग्राया हो;या

(ङ) भारतीय मूल का व्यक्ति जो पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका, पूर्वी अफीका, संयुक्त गणतन्त्र कीनिया, युगांडा, तंजानिया (इससे पूर्व तांगानिका और जंजीबार), जांबिया, मालाबी, जेयरे तथा इथोपिया से भारत में स्थाई रूप से रहने के उद्देश्य से श्राया हो :

उपबन्धित है कि वर्ग (ख),(ग),(घ) और (ङ) से सम्वन्धित वही प्रत्याशी माना जायेगा जिसको भारत सरकार/राज्य सरकार से पावता का प्रमाण-पव जारी किया हो, प्रत्याशी माना जायेगा जिसके बारे में पावता का प्रमाण-पव जारी किया हो, प्रत्याशी माना जायेगा जिसके बारे में पावता का प्रमाण-पव ग्रनिवार्य हो, को भी हिमाचल प्रदेश लोक सेवा ग्रायोग या ग्रन्य भर्ती प्राधिकरण द्वारा ग्रायोजित साक्षात्कार या किसी परीक्षा में बैठने की ग्राज्ञा दी जा सकती है परन्तु उसे नियुक्ति का प्रस्ताव भारत सरकार/हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा पावता का ग्रावश्यक प्रमाण-पव मिलने के बाद ही दिया जायेगा।

सीबी भर्ती की स्थिति में इन पदों हेतु नियुक्ति के लिये चयन मौखिक परीक्षा के ग्राधार पर यदि श्रायोग/भर्ती प्राधिकारी ग्रथवा उचित समझे तो लिखित परीक्षा ग्रथवा व्यवहारिक परीक्षा के ग्राधार पर किया जायेंगा जिसका स्तर/पाठ्यकम इत्यादि ग्रायोग/भर्ती प्राधिकारी द्वारा निर्धारित किया जायेंगा।

उक्त सेवा में नियुक्ति अनुसूचित जातियों/
अनुसूचित जन-जातियों/पिछड़ वर्गों के अन्तर्गत चर्यानत परिवारों इत्यादि के लिये सेवाओं में हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा सनय-सनय पर जारी किये गये आरक्षण सम्बन्धी आदेशों के अधीन होगी।

जहां पर प्रदेश सरकार का यह मत हो कि यह करना जरूरी है या इं। इस तरह से करना है ता उसके कारणों को अंकित कर के हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के 18. विभागीय परीक्षा

परामर्श से लिखित आदेश प्राप्त कर के किसी श्रेणी, वर्ग, व्यक्तियों या पद के नियमों के किसी भी प्रावधान में छूट दी जासकती है।

(i) सेवा के प्रत्येक सदस्य को विभागीय परीक्षा नियम के अन्तर्गत परिवीक्षा अविध या इन नियमों की अधिसूचना के दो वर्ष के भी उर जो भी बाद में हो, विभागीय परीक्षा को पास करना होगा, अन्यथा वह निम्नलिखित का पात नहीं होगा:—

(क) आगामी देय दक्षतारोध पार करने के लिए.

(ख) सेवा में स्थाईकरण,

(ग) ग्रागामी उच्च पद में पदोन्नति :

उपबन्धित है कि यदि एक सदस्य उपर्युक्त ग्रविध के भीतर पदोन्नित के लिए ग्रन्थथा पात बन जाता है, उस की पदोन्नित के लिए विचार ग्रन्थथा किया जाएगा ग्रीर यदि ग्रन्थथा उपर्युक्त पाया जाए, इस विभागीय परीक्षा को पास करने की गर्त पर ग्रस्थायी पदोन्नत कर दिया जाएगा। यदि वह इसे पास करने में ग्रसफल रहता है तो उसे पदावनत किया जा सकता है:

ग्रागे यह भी उपबन्धित है कि ग्रिधिकारी जिसने विभागीय परीक्षा को इन नियमों की ग्रिधिसूचना से पहले किन्हीं ग्रन्य नियमों के ग्रधीन पूरी या ग्रांशिक रूप से पास कर लिया है, उसे पूरी या ग्रांशिक परीक्षा, जैसो भी स्थित हो, पास करनी ग्रंपित नहीं होगी:

ग्रागे उपबन्धित है कि यदि किसी ग्रिधिकारी के लिए इन नियमों के श्रिधिस्चित होने से पहले कोई विभागीय परीक्षा निर्धारित नहीं थी ग्रौर वह ग्रिधिकारी 1 मार्च, 1976 को 45 वर्ष की ग्रायु पार कर चुका हो तो उसे नियमों के ग्रिधीन निर्धारित विभागीय परीक्षा पास करनी ग्रावश्यक नहीं होगी।

(ii) किसी अधिकारी को उसकी सीधे पदोन्नति लाइन के किसी उच्च पद में पदोन्नति होने के उपरान्त उपर्युक्त परीक्षा पास करने की आवश्यकता नहीं होगी, यदि उसने पहले ही इससे निचले राजपतित पद पर उक्त परीक्षा पास

कर ली हो।

(iii) सरकार, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा श्रायोग के परामर्श से विशेष परिस्थितियों में श्रीर लिखित रूप में इसके कारण रिकार्ड कर के विभागीय परीक्षा नियमों के अनुसार व्यक्तियों को किसी भी श्रेणी में या वर्ग को विभागीय परीक्षा में पूर्ण अथवा श्राणिक छूट दे सकती है।

टिप्पणी :-

(i) तथा (ii) श्रेणी के पदों के भर्ती तथा पदोन्तित नियन बनाने सम्बन्धी प्रस्तावों में कमांक 17 में छट की सक्ति जण्ड को कम संख्या 18 में विभागीय परीक्षा में निद्धिट किया गए।

> एस ० एम ७ कंवर, कृषि उत्पादन भ्रायुक्त एवं सचिव ।